Hindustan (Date: - 23/07/2019)

उद्योग की हर योजना की दशा-दिशा देखेंगे अफसर

उद्योग विभाग

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य सरकार से अनुदान लेने वाली इकाइयों की जांच के बाद अब उद्योग विभाग की तमाम योजनाओं की जांच और समीक्षा शुरू की गई है। विभाग ऐसा करके जहां जिला स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ना चाहता है, वहीं योजनाओं को गति देने की भी मंशा है। राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। यह अधिकारी हर महीने दो दिन संबंधित जिलों में रहकर तमाम योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे। इसका सिलसिला शुरू हो चुका है।

राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना में कुछ जिलों से आवेदनों की भरमार के बाद सरकार सारे आवेदनों की जांच करा रही है। उसके साथ ही विभाग की तमाम दूसरी योजनाओं की भी पड़ताल करायी जा रही है। उद्योग विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिलों में जाने वाले पदाधिकारी गड़बड़ी के साथ दिक्कतों को भी देखेंगे।

खास बात यह है कि नोडल अफसरों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्वीकृत प्रस्तावों की अनुदान देने से पूर्व जांच की बात भी कही गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना, हस्तकरघा एवं रेशम क्षेत्र की सभी योजनाओं की स्थलीय जांच करनी है। फूड प्रोसेसिंग स्कीम के तहत स्थापित इकाइयों की भी जमीनी हकीकत देखनी है। इनमें से कितनी कार्यरत हैं, जो कार्यरत हैं, उन्होंने सरकार से लिए गए अनुदान का प्रयोग किया है या नहीं। अनुदान पाने वाली दूसरी सूक्ष्म, मध्यम व बड़ी औद्योगिक इकाइयों को भी इसी कसौटी पर कसा जाना है। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की भी समीक्षा इन अधिकारियों को करनी है। सभी योजनाओं की जांच और समीक्षा की रिपोर्ट फोटो और वीडियो के साथ उद्योग निदेशक को सौंपनी होगी।

रहेगी नजर

- योजनाओं की प्रगति के साथ फर्जीवाड़ा रोकने की हो रही कवायद
- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्वीकृत प्रोजेक्टों को भी देखेंगे नोडल पदाधिकारी

38 जिलों में जांच को भेजे गए नोडल पदाधिकारी

जिला उद्योग केंद्रों पर लंबित कार्यों की होगी समीक्षा

राज्य सरकार की योजनाओं के साथ ही नोडल अफसरों को सभी जनपदों में जिला उद्योग केंद्रों पर लंबित कार्यों की भी समीक्षा करनी है। समस्या का समाधान कराने के साथ ही काम को लटकाने वालों की रिपोर्ट भी देंगे।